Unprofitability In Visakhapatnam Steel Plant

1668. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to accord Visakhapatnam Steel Plant the status of an "Export Oriented Unit";

(b) if so, what are the projection of exports in quantity terms in 1993-94 and 1994-95;

(c) whether it is a fact that the equipment utilisation at Visakhapatnam Steel Plant is not at an optimum level;

(d) what are the reasons for the under utilisation of equipment at this plant; and

(e) whether under utilisation of equipment is the primary cause of unprofitability at this stage?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) : (a) and (b) Management of VSP has suggested that the company may be accorded the status of Export Oriented Unit as per provisions under EXIM Policy, Government of India. VSP has, however, targetted to export 9,00,000 tonnes of saleable steel and 4,00,000 tonnes of pig iron during the current year.

(c) to (e) Production units of Visakhapatnam Steel Plant under Stage-II taking the capacity of 3 million tonnes of crude steel were commissioned in July, 1992. The production units are still in the process of stabilisation. The management has initiated remedial measures to improve the capacity utilisation of the facilities. VSP is expected to achieve 100% capacity utilisation by 1996-97. The losses of VSP are on account of low capacity utilisation and also high incidents of capital related charges.

तकनीकी परामर्शदाता कम्पनियां

1669. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चौधरी हरि सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी परामर्शदाता कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इन कंपनियों ने कुल कितना कारोबार किया;

(ख) इस सम्बंध में गैर-सरकारी एजेंसी की तुलना में सरकारी एजेन्सी के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तकनीकी परामर्शदाता से संबद्ध अनुमनित कार्य का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस (इण्डिया) लि० (मेकन) तथा मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी ऐसी दो प्रमुख तकनीकी परामर्शी कम्पनियां हैं जो इस्पात क्षेत्र में कार्यरत हैं । ऐसी कई अन्य एजेन्सियां हैं जो इस्पात क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में कार्यरत हैं ।

मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी जो निजी क्षेत्र की कम्पनी हैं, के द्वारा किये गए कारोबार का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इस्पात क्षेत्र की सरकारी क्षेत्र की कम्पनी "मेकन" ने वर्ष 1992—93 के दौरान 115 करोड़ रूपये का कुल कारोबार किया ।

(ख) सरकारी मार्ग दर्शनों के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संगठन दोनों को बराबर अवसर दिया जाता है । सरकारी क्षेत्र के संगठनों को तभी तरजीह दी जाएगी, जब अन्य बातें समान हों ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान "सेल" की इकाइयों से मिलने वाले परामर्शी कार्य निम्नानुसार हैं :—

— बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण (सतत कास्टर को शुरू करना तथा हॉट-स्ट्रीप मिल का आधुनिकीकरण)

— भिलाई इस्पात संयंत्र (312 एम^2 का सिन्टर संयंत्र नं०—3, 1×30 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र, और 550 टन दैनिक का आक्सीजन संयंत्र) ।

दिल्ली को सुन्दर बनाया जाना

1670. **डा० नौनिहाल सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी को सुन्दर और हरा-भरा बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों की अब तक क्या भूमिका रही है; और

(ख) राजधानी पर जनसंख्या के भार को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गन्दी बस्ती में न बदल जाए, राजधानी विस्तार योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संवर्धन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी एजेन्सियां राजधानी को सुन्दर और हरा-भरा बनाने के लिये योजनायें बनाने और चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । दिल्ली के मास्टर प्लान में जहां भूमि उपयोग, जनसंख्या घनत्व और कानूनन हरित क्षेत्र का प्रावधान है वहीं अन्य के साथ-साथ स्मारकों, सामाजिक पार्कों और बगीचों तथा दिल्ली के सौन्दर्यकरण सांस्कृतिक विरासत

परिवेश सुधार के लिए निर्मित अन्य स्थलों आदि के संरक्षण परिसंरक्षण मामलों के अध्ययन और सलाह देने के लिये दिल्ली नगर कला आयोग नामक संस्था बनाई गयी है । इसके साथ ही नगर प्राधिकरण के अतिरिक्त जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पार्कों/उद्यानों का विकास और अनुरक्षण करता है दिल्ली विकास प्राधिकरण का बागवानी विभाग भी अपने दायरे के हरे-भरे क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करता है और मास्टर प्लान के हरित क्षेत्र, निकटवर्ती पार्कों और जिला पार्कों का भी विकास करता है । प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले बाल उद्यान और खेल मैदान आदि का भी विकास करता है ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिल्ली के आस-पास के प्राथमिकता वाले शहरों का विकास करने का विचार रखता है । इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार/योजना बोर्ड द्वारा कई परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं । दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिये राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड ने एक विस्तृत निवेश कार्यक्रम तैयार किया है जिसके लिये बोर्ड के राज्य सेक्टर के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उनकी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एन० सी० आर० प्लानिंग बोर्ड के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गये हैं । बोर्ड ने प्राथमिकता शहरों और दिल्ली महानगर क्षेत्र शहरों से संलग्न नई बस्तियाँ बनाने का भी प्रस्ताव किया है ताकि दिल्ली में आबादी को सीमित किया जा सके और राजधानी क्षेत्र का संतुलित और सुनियोजित विकास किया जा सके । इससे दिल्ली में स्लमों की बढ़ोतरी को रोकने में भी मदद मिलेगी जो इस समय मूलतः बाहर से भारी संख्या में लोगों के कारण पैदा हो रही है ।

HUDCO loan to housing Agencies of Gujarat

1671. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that HUDCO loan to housing agencies of Gujarat is reducing year by year;

(b) the amount of loan which has been sanctioned and disbursed by the HUDCO to housing agencies of Gujarat during the last three years and the details thereof;

(c) what are the reasons for decreasing the HUDCO loan to housing agencies of Gujarat; and

(d) whether HUDCO propose to increase loan to housing agencies of Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) No, Sir. As may be seen from the figures given below the loan allocation to Gujarat from HUDCO has been increasing steadily.

HUDCO Loan Assistance to Gujarat

(Rs. in Crores)

Year	Allocation	Sanction	Release
1990—91	40.39	52.62	50.85
1991—92	43.32	43.55	29.16
1992—93	48.63	60.41	58.10

(c) and (d) Question does not arise in view of the above reply.

Allotment of flats under self Financing scheme by DDA

1672. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority has not allotted flats registered under the self financing schemes;

(b) the number of flats which have been allotted to the registrants in different self financing schemes uptil now;

(c) what are the reasons for the delay in allotment of flats under the self financing schemes; and

(d) by when the DDA is expected to clear the back-log registered under self financing schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. According to the DDA under the self financing Scheme initially allocations are made after inviting applications from the registrants from time to time and on completion of the construction of the allocated flats, the specific flat nos. are allotted to the allocatees who have made the payment according to the given schedule.

(b) 61,100.

(c) The flats are offered to the registrants on finalisation of the plans by the Planning/ Engineering Wing of DDA. The last such